>

Title: The Minister of Rural Development laid a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 35th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2008-09), pertaining to the Ministry of Rural Development.

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): मैं लोक सभा बुलेटिन भाग-II दिनांक 1 सितंबर, 2004 के माध्यम से लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश के अनुसरण में ग्रामीण विकास (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित स्थायी समिति (2007-08) की 35वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य रखता हूं।

ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 35वीं रिपोर्ट 17 अप्रैल, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की वर्ष 2008-09 की अनुदान-मांगों की जांच से संबंधित है। समिति की रिपोर्ट में अंतर्विÂट सिफारिशों/ि◌टप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 8.8.2008 को समिति को भेज दी गई थी।

उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा 43 सिफारिशें की गई थीं जहां सरकार की ओर से कार्रवाई करने की मांग की गई थी। ये सिफारिशें मुख्य रूप से राÂट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु सतर्कता एवं निगरानी समिति, सूचना का अधिकार तथा बीपीएल सूची को अंतिम रूप देना आदि से संबंधित योजनाओं से जुड़े मुद्दों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दर्शाई गई है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पठित समझा जाए।

* Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 9343/08.